प्रो. योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने रहेंगे, मिला दूसरा कार्यकाल; ये हैं उपलब्धियां

नई दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। उन्हें आगामी पांच वर्षों के लिए इस प्रतिष्ठित पद पर बने रहने का अवसर मिला है। यह नियुक्ति उनके पहले कार्यकाल में किए गए महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों को दर्शाती है। सिंह ने वर्ष 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति का पद संभाला था। अपने पहले कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विश्वविद्यालय में कई बड़े बदलावों को सफलतापूर्वक लागू किया। इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 का क्रियान्वयन प्रमुख रहा। उन्होंने स्नातक पाठ्यक्रमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए।

बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 234 ● नई दिल्ली ● शनिवार 04 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

सोशल मीडिया पर चाकू लहराकर दबदबा बनाने की कोशिश, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) सोशल मीडिया पर चाकू लहराकर इलाके में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे एक युवक को पटेल नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दिव्यांशु के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चाकू बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी पर पहले से दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर अपराध का महिमामंडन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर निगरानी रख रही है। इसी दौरान पुलिस की निगरानी में एक इंस्टाग्राम अकाउंट सामने आया, जिस पर एक युवक चाकू लहराते हुए तस्वीरें पोस्ट कर रहा था। थाना प्रभारी नवीन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे शादीपुर से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता हासिल करने और इलाके में दबदबा कायम करने के उद्देश्य से चाकू के साथ तस्वीरें पोस्ट की थीं। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच में पता चला कि उसके खिलाफ मोती नगर और पटेल नगर थाने में दो मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके आपराधिक गतिविधि के बारे में जानकारी हासिल कर

केजरीवाल का आरोप: ई20 पेट्रोल जनता पर थोपा, गाड़ियां हो रही हैं खराब, माइलेज भी घटा

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता पर जबरदस्ती ई20 पेट्रोल थोप रही है। उन्होंने दावा किया कि इससे गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और ईंधन की क्षमता (माइलेज) भी कम हो रही है। एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को लेकर जनता में काफी गुस्सा है। 30 जून को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह सिर्फ एक प्रयोग है और आगे की कार्रवाई इसके नतीजों पर निर्भर करेगी। जब यह बात मीडिया और अखबारों में आई, तो केंद्र सरकार पूरी तरह से पीछे हट गई। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा और यह झूठ है। उन्होंने सरकार के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा, और यह किस तरह का प्रयोग है? आपने सभी लोगों और सभी गाड़ियों के लिए इथेनॉल-मिला

हुआ पेट्रोल अनिवार्य कर दिया है, और अब आप कह रहे हैं कि आप प्रयोग कर रहे हैं? क्या आप उन लोगों को मुआवजा देंगे जिनकी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं? केजरीवाल ने दावा किया कि इथेनॉल मिलाने की वजह से गाड़ियाँ खराब हो रही हैं और उनके पार्ट्स को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश मोदी सरकार के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब बन गया है। लोगों पर जबरदस्ती ई20 पेट्रोल थोपा जा रहा है। इथेनॉल की वजह से लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, पार्ट्स को नुकसान पहुँच रहा है और माइलेज भी कम हो रहा है। लोग बहुत नाराज हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप इसे उन पर क्यों थोप रहे हैं? आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? जनता ने ही आपको वोट दिया है। उनके वोट का सम्मान करना और उनकी बात सुनना आपका कर्तव्य है। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की योजना की घोषणा की और जनता से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने जा रहा हूं। आप सभी कृपया मुझे डीएम करें और टिप्पणी करके बताएं कि मुझे पत्र में क्या लिखना चाहिए। आप नेता की ये टिप्पणियाँ ई20 पेट्रोल का गाड़ियों पर पड़ने वाले असर को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद आईं। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी इस हफ्ते की शुरुआत में केंद्र सरकार की आलोचना की थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बिना पर्याप्त सबूत, सार्वजनिक सलाह-मशविरे या आम सहमति के इथेनॉल-मिश्रित ईंधन पेश करके 3.6 करोड़ भारतीयों को एक प्रयोग का हिस्सा बना दिया है। खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने माना है कि वह अभी भी इथेनॉल मिलाने के असर का आकलन कर रही है, जबकि उसने बिना पर्याप्त सार्वजनिक सलाह-मशविरे या आम सहमति के ही यह नीति लागू कर दी है।

चीन के सामने झुक रही सरकार? कांग्रेस का दावा- चीनी कंपनियों सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने की मिली अनुमति

नई दिल्ली। (वेबवार्ता) कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार का चीन के सामने टेकने का सिलसिला जारी है, जिससे देश के उद्योगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई)। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत सरकार ने चीन की उन चार बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनियों को अहम सरकारी बिजली परियोजनाओं के टेंडर में हिस्सा लेने की अनुमति दी है, जिनकी फैक्ट्रियां भारत में हैं। अपने पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा, मोदी सरकार का चीन के सामने सोच-समझकर झुकने का सिलसिला जारी है। इसी समय भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे देश के उद्योगों का बड़ा नुकसान हो रहा है, खासकर एमएसएमई। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की उकसाने वाली गतिविधियां लगातार जारी हैं। रमेश ने दावा किया कि मेडोग (तिब्बत का दूरदराज क्षेत्र का जिला) में दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना का निर्माण जारी है। इससे ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी भारत की जल सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में भारत ने अपनी पारंपरिक गश्त और पशु चराने के अधिकार छोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा, 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट दे दी थी। रमेश के अनुसार, यह उस समय हुआ, जब लद्दाख में भारत के 20 बहादुर जवानों का बलिदान हुआ था। रमेश ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गतिविधियों में चीन की अहम भूमिका थी। उनके अनुसार, इस बात को उप सेना प्रमुख ने स्वीकार किया था और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। इसके बावजूद भी सरकार का चीन

शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को दिया बड़ा झटका, प्राइवेट बिजली कंपनियों के कैग ऑडिट पर लगाई रोक

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार द्वारा तीन प्राइवेट बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कैग ऑडिट के आदेश पर रोक लगा दी। यह मामला उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले रेगुलेटरी एसेट्स (आरए) के तौर पर वर्षों में जमा हुए भारी-भरकम 38,500 करोड़ रुपये से जुड़ा है। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। बेंच ने कहा कि बिजली रेगुलेटर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) के कैग को नियुक्त करने के फैसले की कानूनी वैधता पर सवाल उठते हैं, जिन पर न्यायिक निर्णय की जरूरत है। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को झटका देते हुए शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, अगले आदेश तक ऑडिट के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति के संबंध में अपेलट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपटेल) के निर्देश पर रोक रहेगी। इस दौरान कैग भी ऑडिट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएगा।

शीर्ष अदालत एपटेल के अप्रैल के फैसले के खिलाफ डीईआरसी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एपटेल ने अपने फैसले में कहा था कि ऑडिट का काम कैग को सौंपना कानूनी ढांचे के खिलाफ है और रेगुलेटर को ऑडिट के लिए एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करने का निर्देश दिया था। डिस्कॉम को नोटिस जारी करते हुए बेंच ने कहा, यह सिविल अपील सीधे तौर पर इस मुद्दे से जुड़ी है कि क्या डीईआरसी द्वारा कैग के माध्यम से वितरण कंपनियों के ऑडिट की प्रक्रिया शुरू करना कानूनी रूप से सही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 15 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। उस दिन डीईआरसी की याचिका पर एक रेगुलर बेंच सुनवाई करेगी, जिसने पिछले साल अगस्त में फैसला सुनाया था।

सोनम को फिलहाल राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली । राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने पहली नजर में हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले पर कुछ प्रारंभिक टिप्पणियां हैं, लेकिन चूंकि सोनम पहले ही जेल से रिहा हो चुकी है, इसलिए इस स्तर पर जमानत पर रोक नहीं लगाई जा सकती। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के फैसले को बेहद चौंकाने वाला बताया। उन्होंने अदालत को बताया कि यह मामला एक सुनियोजित हत्या का है, जिसमें हनीमून पर गए राजा रघुवंशी की हत्या कर शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया था। उनके अनुसार, इस वारदात में सोनम समेत अन्य आरोपी भी शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि हत्या के बाद सोनम फरार हो गई थीं और बाद में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार की गई थीं। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि मामले में 94 गवाह हैं और मुकदमे की सुनवाई जारी है।

क्या टाइपिंग की गलती जमानत का आधार बन गई?

सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने केवल इस आधार पर सोनम को जमानत दी कि गिरफ्तारी दस्तावेजों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) की जगह गलती से धारा 403(1) लिख दी गई थी। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता में धारा 403 अस्तित्व में ही नहीं है और यह सिर्फ टाइपिंग की त्रुटि थी। मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी के समय आरोपी को हत्या के आरोप और गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट रूप से

बताए थे। इसलिए केवल एक तकनीकी गलती के आधार पर जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर क्या टिप्पणी की?

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरश ने कहा कि पहली नजर में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर अदालत के मन में कुछ सवाल हैं। उन्होंने आरोपी पक्ष से पूछा कि जब पहले की जमानत याचिकाओं में गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाने का मुद्दा नहीं उठाया गया, तो बाद में अचानक यही आधार कैसे बना। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या केवल गलत धारा लिखे जाने के कारण जमानत देना सही था, जबकि पहले मेरिट के आधार पर राहत से इनकार किया जा चुका था। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि सोनम पहले ही रिहा हो चुकी हैं, इसलिए फिलहाल जमानत पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया जाएगा।

क्या आरोपी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी?

सोनम रघुवंशी की ओर से पेश वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार उन्हें कभी सही तरीके से नहीं बताए गए। उन्होंने यह भी कहा कि सोनम पर सख्त शर्तें लागू हैं और उन्हें शिलांग में ही रहना होगा, इसलिए उनके फरार होने की आशंका नहीं है। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है और ऐसे में उन्हें लगातार जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि जमानत केवल तकनीकी आधार पर दी गई है, तो राय सरकार के पास कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे कदम उठाने का अधिकार बना रहेगा। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि अब चूंकि आरोपी रिहा हो चुकी है, इसलिए फिलहाल जमानत पर रोक लगाना उचित नहीं होगा।

क्या है राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस का पूरा मामला?

राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 12 मई 2025 को हुई थी। 23 मई को दोनों हनीमून मनाने मेघालय गए, जहां से वे अचानक लापता हो गए। बाद में उनकी किराये की स्कूटी लावारिस मिली और 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद किया गया। इसके बाद 8 जून को सोनम उत्तर प्रदेश में मिलीं। जांच में मेघालय पुलिस ने आरोप लगाया कि पति की हत्या पहले से बनाई गई साजिश का हिस्सा थी, जिसमें सोनम और उनके कथित प्रेमी राज कुशवाहा समेत अन्य आरोपी शामिल थे। पुलिस इस मामले में 700 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और दावा किया है कि हत्या पूरी योजना के तहत की गई थी।

सम्पादकीय...

इथेनॉल और गाड़ी का...

भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने की सरकारी नीति एक बार फिर चर्चा में है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में इथेनॉल मिश्रित ईंधन का समर्थन करते हुए कहा कि इथेनॉल का उपयोग केवल सामान्य वाहनों में ही नहीं, बल्कि रेसिंग कारों में भी किया जाता है। उनके अनुसार, इथेनॉल इंजन की गति बढ़ाने, बेहतर एक्सीलरेशन देने और नॉकिंग (इंजन में होने वाली अनियमित कंपन) को कम करने में सहायक होता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अधिक इथेनॉल मिश्रण से माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इसके कई अन्य लाभ इस कमी की भरपाई करते हैं। मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई, जिसका सीधा असर भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियों पर पड़ा। सरकार के अनुसार, जून 2026 तक पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लागत से कम कीमत पर बेचने के कारण तेल कंपनियों को लगभग 74,781 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। अप्रैल से जून 2026 की अवधि में कुल अंडर-रिकवरी 1.88 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गई। ऐसी परिस्थितियों में सरकार का मानना है कि पेट्रोल में इथेनॉल का अधिक मिश्रण भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। भारत अपनी पेट्रोलियम आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार और आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। यदि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जाती है तो कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और आयात बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्का तथा अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक नवीकरणीय और अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन है। इसके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड सहित कई प्रदूषक गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का कोई भी निर्णय व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही लेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में ई-20 यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध है। यदि भविष्य में इसे बढ़ाकर ई-25 किया जाएगा तो उससे पहले भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा अन्य संबंधित संस्थाओं से व्यापक परामर्श और तकनीकी परीक्षण किए जाएंगे। हाल के दिनों में यह आशंका भी जताई गई थी कि अधिक इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के उपयोग से वाहनों का बीमा प्रभावित हो सकता है। इस पर मंत्री ने कहा कि बीमा कंपनियां पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। उन्होंने अफवाहों से बचने और प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। सरकार का दृष्टिकोण यह भी है कि भारत की परिवहन व्यवस्था केवल एक तकनीक पर आधारित नहीं होगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहन, इथेनॉल मिश्रित ईंधन वाले वाहन, हाइब्रिड वाहन और सीएनजी वाहन सभी के लिए पर्याप्त स्थान है। भारत जैसे विशाल देश में ऊर्जा परिवर्तन एक बहु-आयामी प्रक्रिया होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का समानांतर विकास आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर भी इथेनॉल मिश्रण को व्यापक स्वीकार्यता मिल रही है। अमेरिका में ई-10 व्यापक रूप से उपयोग में है और ई-15 का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वहां लचीले फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ई-85 तक के मिश्रण पर चल सकते हैं। ब्राजील इस क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश माना जाता है, जहां ई-27 अनिवार्य है और बड़ी संख्या में वाहन 100 प्रतिशत इथेनॉल पर भी चलने में सक्षम हैं। कनाडा, जापान, थाईलैंड और कई यूरोपीय देशों ने भी अपने ईंधन मिश्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक अपनाया है। भारत का इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम भी पिछले एक दशक में उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ा है। जहां 2013-14 में जहां इथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 38 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष थी, वहीं अब यह बढ़कर लगभग 2,000 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष हो चुकी है। इसी प्रकार इथेनॉल मिश्रण का स्तर 1.5 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2025 में 20 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस कार्यक्रम से अब तक भारत को 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। किसानों को इथेनॉल उत्पादन के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। इसके अलावा 310 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का आयात टाला जा सका है और लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। इससे स्पष्ट है कि यह योजना केवल ऊर्जा नीति नहीं, बल्कि कृषि, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से भी सीधे जुड़ी हुई है। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इथेनॉल मिश्रण के विस्तार के साथ कुछ चुनौतियों पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। अधिक इथेनॉल मिश्रण के लिए अनुकूल इंजन तकनीक, पर्याप्त उत्पादन क्षमता, जल संसाधनों का संतुलित उपयोग तथा खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों पर निरंतर निगरानी रखनी होगी। यदि इन चुनौतियों का वैज्ञानिक समाधान किया जाता है तो भारत स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। अंततः, हरदीप सिंह पुरी का बयान केवल इथेनॉल की तकनीकी विशेषताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का भी संकेत देता है।

बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच इथेनॉल मिश्रित ईंधन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभर रहा है। यदि सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक संस्थान और किसान मिलकर इस दिशा में संतुलित और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि स्वच्छ पर्यावरण, किसानों की आय में वृद्धि और विदेशी मुद्रा की बचत जैसे अनेक लक्ष्यों को भी एक साथ प्राप्त कर सकेगा।

अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से मोजतबा खामेनेई की दूरी

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के निधन के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में उनके विशाल पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं तथा लाखों लोग अंतिम श्रद्धांजलि देने की तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि, सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि उनके पुत्र और वर्तमान सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता के अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं होंगे। यह जानकारी भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हाकिम इलाही ने दी है। उनके अनुसार, इजराइल से संभावित खतरे और निगरानी की आशंका को देखते हुए मोजतबा का सार्वजनिक रूप से अंतिम संस्कार में शामिल होना अत्यंत जोखिमपूर्ण माना गया है। यह फैसला केवल एक पारिवारिक निर्णय नहीं, बल्कि ईरान की वर्तमान सुरक्षा स्थिति और पश्चिम एशिया की जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों को भी दर्शाता है। सामान्यतः इस्लामी परंपरा में किसी व्यक्ति के निधन के बाद 24 घंटे के भीतर दफनाने की परंपरा है, लेकिन युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में विशेष व्यवस्था की गई। पिछले कुछ महीनों से अंतिम संस्कार के समय और स्वरूप को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थीं। अली खामेनेई कई दशकों तक ईरान की राजनीति और धार्मिक व्यवस्था के सबसे प्रभावशाली नेता रहे। उन्होंने ईरान की विदेश नीति, रक्षा रणनीति और क्षेत्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। उनके निधन के बाद मोजतबा खामेनेई को सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारी मिली, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव को नियंत्रित करना है। मोजतबा खामेनेई का अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से शामिल न होना इस बात का संकेत है कि ईरान अपने शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। हाल के महीनों में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, ड्रोन हमलों, साइबर गतिविधियों और खुफिया अभियानों ने सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। ऐसे माहौल में किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में सर्वोच्च नेता की उपस्थिति को संभावित सुरक्षा जोखिम माना जा रहा है। अंतिम संस्कार में भारत की ओर से भी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। सूत्रों के अनुसार, बिहार के राज्यपाल जनरल सैयद हसनैन, विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा तथा पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ईरान जाकर भारत सरकार और भारतीय राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, हालांकि प्रधानमंत्री के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने की संभावना कम बताई गई है। भारत और ईरान के संबंध ऐतिहासिक और रणनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार बंदरगाह, मध्य एशिया तक संपर्क तथा सांस्कृतिक संबंधों के कारण दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बना हुआ है। ऐसे में भारत का प्रतिनिधिमंडल अंतिम संस्कार में शामिल होना दोनों देशों के पारंपरिक संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में पश्चिम एशिया की बदलती सुरक्षा स्थिति भी महत्वपूर्ण है। पिछले महीने ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिससे क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद जगी थी। लेकिन समझौते के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं। हाल के दिनों में ईरान ने दावा किया कि होरमुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा एक वाणिज्यिक जहाज निर्धारित मार्ग से भटक गया था, जिसके बाद उसे निशाना बनाया गया। इसके जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए, जिसकी दोनों देशों ने कड़ी निंदा की। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि शांति समझौते के बावजूद क्षेत्रीय तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में स्थिति अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे रही है। कतर की राजधानी दोहा में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच अलग-अलग बैठकें हुईं। इन बैठकों में 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) से जुड़े कई मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति होने की जानकारी सामने आई है। यदि यह वार्ता सफल रहती है तो पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान की आंतरिक और बाहरी नीतियों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व में ईरान किस प्रकार अमेरिका, इजराइल और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाता है, यह आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति की दिशा तय करेगा। वहीं, अंतिम संस्कार में उनकी अनुपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आधुनिक दौर में सुरक्षा संबंधी खतरे केवल युद्धक्षेत्र तक सीमित नहीं रह गए हैं। ड्रोन तकनीक, साइबर निगरानी और खुफिया अभियानों ने विश्व नेताओं की सार्वजनिक गतिविधियों को पहले की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील बना दिया है। इसलिए कई बार राजनीतिक और धार्मिक परंपराओं से ऊपर सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ती है। अंततः, अली खामेनेई का अंतिम संस्कार केवल एक राष्ट्रीय शोक समारोह नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति, सुरक्षा चुनौतियों और कूटनीतिक समीकरणों का भी महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है। मोजतबा खामेनेई का सुरक्षा कारणों से अंतिम संस्कार से दूर रहना इस बात का संकेत है कि ईरान अभी भी गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। दूसरी ओर, भारत सहित विभिन्न देशों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद ईरान अपने आंतरिक प्रशासन, क्षेत्रीय रणनीति और वैश्विक कूटनीति को किस दिशा में आगे बढ़ाता है।

व्हाट्सएप का नया फीचर

मानव स्वभाव बहुत जिज्ञासु होता है। जैसे ही सोशल मीडिया की क्रांति आई मनुष्य के लिए दुनियाभर में तुरंत सम्पर्क करना संभव हो गया। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात करना पड़ोसी से बात करने जैसा हो गया है। घर की चारदीवारी में कम्प्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल ने जगह बना ली। चाहे निजी उद्देश्य हो या व्यावसायिक संचार मनुष्य का काम आसान हो गया है। सोशल मीडिया साइटें संचार का एक महत्वपूर्ण घटक बन गई। सोशल मीडिया साइटें भौगोलिक दूरी के बावजूद दोस्तों, परिवार और समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ने का अवसर प्रदान करती हैं लेकिन सोशल मीडिया की शक्ति का दुरुपयोग होना इतना बढ़ चुका है कि अब इस पर नियंत्रण के उपाय खोजे जा रहे हैं। सोशल मीडिया कम्पनियां नए-नए फीचर लाती रहती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़े रहें। कम्पनियां साइबर सुरक्षा की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देतीं। अब व्हाट्सएप का नया फीचर विवादों से घिर गया है। व्हाट्सएप ने मैसेजिंग सेवा के 'यूजर नेम' फीचर को शुरू किया जिसमें वह धीरे-धीरे उपयोगकर्ताओं को पहली बार किसी अन्य उपयोगकर्ता से सम्पर्क करते समय अपने उपयोगकर्ता का नाम चुनने और अपना फोन नम्बर छुपाने की सुविधा देगा। यह एक वैकल्पिक विशिष्ट पहचानकर्ता है जिसे उपयोगकर्ता अपने व्हाट्सएप खाते के लिए चुन सकता है। इसका उपयोग अन्य लोग भी उसे संदेश भेजने या कॉल करने के लिए कर सकते हैं जिससे उनका फोन नम्बर गोपनीय रहेगा। जब विशेषज्ञों ने इस फीचर के गलत इस्तेमाल की आशंकाएं जताईं तो गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के समक्ष चिन्ता व्यक्त की। तब सरकार ने मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार इस नए फीचर के जोखिम का मूल्यांकन करेगी और देखेगी कि क्या यह मौजूदा कानूनी ढांचे का उल्लंघन करता है। सरकार ने कम्पनी को निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक फीचर को लॉन्च न किया जाए। ऐसी संभावना है कि कुछ शरारती तत्व प्रमुख हस्तियों, संस्थानों और संगठनों से मिलते-जुलते यूजरनेम या उनके मिलते-जुलते नामों का इस्तेमाल करके दूसरे यूजर्स को संदेश भेज सकते हैं और खुद को कोई और बता सकते हैं। जो लोग तकनीकी रूप से इतने जानकार नहीं हैं कि अंतर समझ सकें, उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हमने पहले ही देखा है कि शरारती तत्व व्हाट्सएप के जरिए डिजिटल गिरफ्तारियों जैसे फर्जीवाड़े कर रहे हैं और यह ?फीचर उन्हें और भी मदद कर सकता है। एक बयान में व्हाट्सएप ने कहा कि वह इस साल के अंत तक धीरे-धीरे इन सुविधाओं को शुरू करने की योजना बना रहा है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि उसने सुरक्षा उपाय किए हैं। नकली पहचान से बचाव के लिए हमने सबसे चर्चित नामों-जैसे सार्वजनिक हस्तियां, सरकारी संस्थाएं, मशहूर हस्तियां, सत्यापित मेटा खाते को सुरक्षित रखा है, ताकि उन पर केवल उनके असली मालिक ही दावा कर सकें और जाने-माने नामों से मिलते-जुलते नामों को भी सुरक्षित रखा गया है। यद्यपि व्हाट्सएप का कहना है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अभी भी फोन नम्बर की जरूरत होगी और उसने धोखाधड़ी से बचाव के लिए कई सुरक्षा उपाय शामिल किए हैं लेकिन विशेषज्ञों ने गम्भीर चिंताएं व्यक्त की हैं। साइबर ठग व्हाट्सएप पर यूजर नेम का गलत इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दे सकते हैं। स्कैमर्स फोन नम्बर छुपाकर लोगों से सम्पर्क करेंगे। इससे इन्वेस्टमेंट स्कैम, फिशिंग और नौकरी स्कैम जैसे फ्रॉड बढ़ेंगे। व्हाट्सएप पर अभी मोबाइल नम्बर दिखाई देता है जिससे उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है।

कीव पर रूस का सबसे घातक हमला- बढ़ते युद्ध, मानवीय संकट और वैश्विक चिंता

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर बेहद भयावह मोड़ पर पहुंच गया है। गुरुवार तड़के रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर वर्ष 2026 का सबसे बड़ा और सबसे घातक हवाई हमला किया। इस हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, 91 से अधिक लोग घायल हुए और शहर की लगभग 130 इमारतों को नुकसान पहुंचा। यह हमला केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानवीय संकट के लिहाज से भी अत्यंत गंभीर माना जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि ढाई वर्ष से अधिक समय से जारी यह युद्ध समाप्त होने के बजाय लगातार और अधिक विनाशकारी होता जा रहा है।

यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार, रूस ने एक ही रात में 74 मिसाइलें और 496 ड्रोन दागे। इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल इस युद्ध के सबसे बड़े संयुक्त हवाई अभियानों में से एक माना जा रहा है। राजधानी कीव के कई इलाकों में विस्फोटों की आवाजें लगातार सुनाई देती रहीं और पूरे शहर में धुएं के घने बादल छा गए। आपातकालीन सेवाओं की टीमें घंटों तक मलबे में दबे लोगों को निकालने और आग बुझाने में जुटी रहीं। सबसे अधिक नुकसान शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित एक नौ मंजिला आवासीय इमारत को हुआ। एक शक्तिशाली मिसाइल सीधे इमारत से टकराई, जिससे उसकी 64 आवासीय इकाइयां पूरी तरह नष्ट हो गईं। मलबे में कई परिवार फंस गए और राहत-बचाव दलों को जीवित लोगों की तलाश के लिए लंबे समय तक अभियान चलाना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की कई इमारतों की खिड़कियां और दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आयरलैंड की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और तुरंत कीव लौट आए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा क्षतिग्रस्त आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। जेलेंस्की ने इस हमले के लिए रूस को

> **युद्ध का मानसिक प्रभाव भी समाज पर गहराई से दिखाई दे रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध का असर केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है। वैश्विक ऊर्जा बाजार, खाद्यान्न आपूर्ति, तेल और गैस की कीमतें तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी इस संघर्ष से प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि विश्व समुदाय लगातार युद्धविराम और कूटनीतिक समाधान की अपील कर रहा है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आ सका है। अंततः, कीव पर रूस का यह हमला वर्ष 2026 का सबसे घातक हमला बनकर सामने आया है। यह घटना दर्शाती है कि युद्ध अब और अधिक आक्रामक तथा विनाशकारी चरण में प्रवेश कर चुका है।**

जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यदि पश्चिमी देशों द्वारा वादा किए गए आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली समय पर उपलब्ध करा दी जाती, तो इतनी बड़ी तबाही को रोका जा सकता था। उन्होंने अपने सहयोगी देशों से अपील की कि वे केवल घटनाओं को देखते न रहें, बल्कि यूक्रेन की रक्षा के लिए तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। यूक्रेनी वायुसेना ने भी स्वीकार किया कि इस बार रूस ने बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया। साथ ही यह भी बताया कि पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी के कारण कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट नहीं किया जा सका। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली की सीमित उपलब्धता ने इस हमले के प्रभाव को और अधिक गंभीर बना दिया। दूसरी ओर, रूस ने दावा किया कि उसका हमला केवल यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, ऊर्जा अवसंरचना और हवाई अड्डों को निशाना बनाकर किया गया। मॉस्को का कहना है कि यह कार्रवाई हाल ही में रूस के भीतर हुए यूक्रेनी ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। इससे एक दिन पहले यूक्रेन ने रूस के निज़नी नोवगोरोद क्षेत्र स्थित एक बड़े तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया था, जिसे रूस के ऊर्जा ढांचे के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

रूसी सरकार के अनुसार, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हमलों की पूरी जानकारी दी गई है और उन्होंने सैन्य अभियान को जारी रखने का संकेत दिया है। क्रेमलिन का कहना है कि जब तक रूस अपने रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक सैन्य दबाव और बढ़ाया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष फिलहाल समाप्त होने की संभावना कम दिखाई देती है। कीव पर हुए इस बड़े हमले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर लगातार हो रहे हमलों की निंदा करते हुए इसे अत्यंत चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाने वाली ऐसी घटनाएं अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून की भावना के विरुद्ध हैं और युद्ध में आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने भी इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि रूस के सैन्य-औद्योगिक ढांचे का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यूरोपीय देशों का मानना है कि आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाकर ही रूस पर युद्ध समाप्त करने के लिए प्रभावी दबाव बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में रूस और यूक्रेन दोनों ने एक-दूसरे के भीतर लंबी दूरी तक मार करने वाले हमलों की संख्या बढ़ा दी है। ड्रोन, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों का लगातार उपयोग इस युद्ध को और अधिक जटिल तथा खतरनाक बना रहा है। अब युद्ध केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों देशों के प्रमुख शहर और रणनीतिक प्रतिष्ठान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस संघर्ष का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ रहा है। हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं, बड़ी संख्या में आवासीय इमारतें नष्ट हो चुकी हैं और ऊर्जा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी गंभीर असर पड़ा है।

लगातार हमलों के कारण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का जीवन अत्यंत कठिन हो गया है। युद्ध का मानसिक प्रभाव भी समाज पर गहराई से दिखाई दे रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध का असर केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है। वैश्विक ऊर्जा बाजार, खाद्यान्न आपूर्ति, तेल और गैस की कीमतें तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी इस संघर्ष से प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि विश्व समुदाय लगातार युद्धविराम और कूटनीतिक समाधान की अपील कर रहा है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आ सका है। अंततः, कीव पर रूस का यह हमला वर्ष 2026 का सबसे घातक हमला बनकर सामने आया है। यह घटना दर्शाती है कि युद्ध अब और अधिक आक्रामक तथा विनाशकारी चरण में प्रवेश कर चुका है। यदि दोनों पक्षों के बीच शीघ्र किसी राजनीतिक समाधान की दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाले समय में मानवीय संकट और भी गंभीर हो सकता है। ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी केवल निंदा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि शांति स्थापना, मानवीय सहायता और कूटनीतिक पहल को भी समान प्राथमिकता देनी होगी, ताकि निर्दोष नागरिकों की जान बचाई जा सके और इस लंबे संघर्ष का स्थायी समाधान खोजा जा सके।

क्या शिक्षा सेवा है या बाज़ार? स्कूलों में कॉपी- किताब

वैश्विक स्तरपर भारत में प्रत्येक वर्ष जुलाई का महीना लाखों करोड़ों विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत का प्रतीक होता है। नई कक्षाएँ,नए सपने, नई पुस्तकें,नई वर्दी और नई उम्मीदें, ये सब मिलकर शिक्षा का उत्सव रचते हैं। किंतु इसी उत्सव के बीच एक ऐसी समस्या लगातार गहराती जा रही है,जो शिक्षा के मूल उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। देश के अनेक निजी विद्यालयों में अभिभावकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष दुकान अथवा स्वयं विद्यालय से ही पुस्तकें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म, जूते, बैग तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए बाध्य किए जाने की शिकायतें वर्षों से सामने आती रही हैं।इससे शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानार्जन से हटकर व्यावसायिक गतिविधि का रूप लेता दिखाई देता है। 2 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र विधानसभा में शालेय शिक्षण मंत्री ने इस विषय पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र विद्यार्थी तक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में ही आवश्यक सामग्री समय पर पहुँचाना है। यदि किसी जिले या विद्यालय में वितरण में देरी अथवा अनियमितता होती है, तो उसकी जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी निजी विद्यालय अभिभावकों को किसी एक विशेष दुकान से पुस्तकें, यूनिफॉर्म या अन्य शाला सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह वक्तव्य केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक नीति- संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए।दरअसल, भारत का संविधान शिक्षा को समान अवसर का आधार मानता है। शिक्षा का अधिकार केवल विद्यालय में प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना भी राज्य की जिम्मेदारी है जिसमें आर्थिक स्थिति किसी बच्चे की शिक्षा में बाधा न बने। यदि किसी अभिभावक को बाजार में उपलब्ध समान गुणवत्ता की पुस्तकें या यूनिफॉर्म कम कीमत पर मिल सकती हैं, फिर भी उसे विद्यालय द्वारा निर्धारित विक्रेता से ही खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है,तो यह प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता अधिकार और शिक्षा की नैतिकता, सटीक रूप से तीनों के विरुद्ध है। साथियों, देश के अनेक शहरों और कस्बों में यह देखा गया है कि कुछ विद्यालय विशेष प्रकाशकों से समझौता कर ऐसी पुस्तकें निर्धारित कर देते हैं जो सामान्य बाजार में उपलब्ध नहीं होतीं।कई विद्यालय अपनी अलग अभ्यास पुस्तिकाएँ भी अनिवार्य कर देते हैं। इसी प्रकार यूनिफॉर्म के लिए भी एक निश्चित दुकान तय कर दी जाती है। परिणामस्वरूप अभिभावकों के पास विकल्प समाप्त हो जाता है और उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार एक ही गुणवत्ता की सामग्री खुले बाजार में काफी कम मूल्य पर उपलब्ध होती है, लेकिन विद्यालय की शर्तों के कारण उसका लाभ नहीं मिल पाता।भारत जैसे देश में,जहाँ बड़ी संख्या में परिवार मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग से आते हैं, शिक्षा पर होने वाला अतिरिक्त व्यय परिवार की आर्थिक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। कई अभिभावकों को बच्चों की फीस, परिवहन, पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य खर्चों के लिए ऋण लेना पड़ता है। यदि शैक्षणिक सामग्री की खरीद में प्रतिस्पर्धा और विकल्प समाप्त कर दिए जाएँ, तो यह आर्थिक बोझ और बढ़ जाता है। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना है, न कि आर्थिक असमानता को और गहरा करना। साथियों, शासकीय विद्यालयों की स्थिति इससे भिन्न होते हुए भी चुनौतियों से मुक्त नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें,यूनिफॉर्म,बैग तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बड़ी धनराशि खर्च करती हैं।कई राज्यों में वितरण प्रक्रिया में देरी,आपूर्ति संबंधी समस्याएँ अथवा प्रशासनिक लापरवाही जैसी शिकायतें सामने आती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री द्वारा अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि निर्धारित समय पर सामग्री विद्यार्थियों तक पहुँचेगी, तभी सरकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा।आज आवश्यकता केवल सामग्री उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी है। यदि पुस्तकें सत्र शुरू होने के कई सप्ताह बाद मिलती हैं, तो विद्यार्थी प्रारंभिक अध्ययन से वंचित हो जाते हैं। यदि यूनिफॉर्म समय पर नहीं मिलती, तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को सामाजिक असहजता का सामना करना पड़ता है। इसलिए वितरण व्यवस्था का वैज्ञानिक और डिजिटल प्रबंधन समय की मांग है। साथियों, यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में शिक्षा का निजीकरण तेजी से बढ़ा है। निजी विद्यालयों ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन शिक्षा सेवा और व्यावसायिक गतिविधि के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। अधिकांश निजी विद्यालय नियमों का पालन करते हैं, किंतु कुछ संस्थानों की गलत कार्यप्रणालियाँ पूरे निजी शिक्षा क्षेत्र की छवि को प्रभावित करती हैं। इसलिए नियमों का सम्मान और निष्पक्ष पालन आवश्यक है।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि विद्यालय केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने का केंद्र नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों का भी निर्माण करते हैं। यदि विद्यालय स्वयं पारदर्शिता, निष्पक्षता और उपभोक्ता अधिकारों का सम्मान नहीं करेंगे, तो विद्यार्थियों में इन मूल्यों का विकास कैसे होगा? शिक्षा संस्थानों का आचरण स्वयं विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा पाठ होता है। साथियों, अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि किसी विद्यालय द्वारा किसी विशेष दुकान से सामग्री खरीदने का दबाव बनाया जाता है, तो अभिभावकों को सामूहिक रूप से विद्यालय प्रबंधन से संवाद करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित शिक्षा अधिकारी अथवा सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी के समक्ष शिकायत भी प्रस्तुत की जा सकती है। जागरूक नागरिक ही पारदर्शी व्यवस्था की नींव होते हैं।आज डिजिटल तकनीक इस समस्या का व्यावहारिक समाधान भी प्रस्तुत करती है। प्रत्येक विद्यालय अपनी पुस्तक सूची, यूनिफॉर्म का डिज़ाइन, आवश्यक सामग्री और उनकी विशिष्टताएँ सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध करा सकता है। इससे अभिभावक किसी भी अधिकृत विक्रेता से निर्धारित मानकों के अनुरूप सामग्री खरीद सकेंगे। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कीमतें नियंत्रित रहेंगी और पारदर्शिता सटीकता से स्वतः स्थापित होगी। साथियों, राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी नीति विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान हो कि विद्यालय किसी एक दुकान, विक्रेता या प्रकाशक से खरीद को अनिवार्य नहीं बना सकेंगे।विद्यालय केवल गुणवत्ता और विनिर्देश निर्धारित करें,खरीद का विकल्प अभिभावकों के पास रहे। यदि कोई विशेष सामग्री विद्यालय द्वारा तैयार की गई हो,तो उसकी कीमत, लागत और वितरण प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए।उपभोक्ता अधिकारों के दृष्टिकोण से भी यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के विक्रेता से वस्तु खरीदने का अधिकार है। यदि किसी संस्था द्वारा यह स्वतंत्रता

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार घाती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होगा। (DELHIN/2019/78863)

ठहाकों के बीच बादशाह प्रेमी की हास्य रचनाओं ने समाज को दिखाया आईना

- येष्ठ पूर्णिमा पर दो दिवसीय धार्मिक आयोजन
- हास्य कवि की प्रस्तुतियों पर देर शाम तक गूंजती रहीं तालियां
- विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा, सांस्कृतिक आयोजन नई पीढ़ी को परंपरा से जोड़ते हैं

पटहेरवा कुशीनगर।

तमकुही विकास खंड के सेमरा हर्दोपट्टी के बेलही कुटी परिसर में येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय धार्मिक आयोजन का समापन मंगलवार की सायं हास्य, व्यंग्य और सांस्कृतिक रंगों के बीच हुआ। अंतिम सत्र में आयोजित कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध हास्य कवि बादशाह तिवारी प्रेमी ने अपनी सशक्त प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि देर शाम तक श्रोता ठहाकों और तालियों के बीच डूबे रहे।

उनकी व्यंग्य रचनाओं ने जहां भरपूर मनोरंजन किया, वहीं सामाजिक विसंगतियों पर भी सार्थक संदेश दिया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ वीर हनुमान की वंदना और धार्मिक काव्य पाठ से हुआ। इसके बाद बादशाह तिवारी प्रेमी ने अपनी चर्चित व्यंग्य प्रस्तुति परिचय व कुकुर भोज सुनाई। विवाह समारोहों में बढ़ते बुफे सिस्टम और बदलती सामाजिक प्रवृत्तियों पर किए गए उनके तीखे लेकिन सहज व्यंग्य ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। कई अवसरों पर पूरा पंडाल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने किया।

उन्होंने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं, संस्कारों और सामाजिक समरसता को मजबूत करने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने और उससे जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। आयोजक महंत श्यामदास उर्फ बाबा बालक दास ने सभी अतिथियों, कवियों और श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आशीर्वाद दिया। उन्होंने सभी के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की।

कार्यक्रम का समापन भंडारा एवं प्रसाद वितरण के साथ हुआ। संचालन चंदन सिंह ने किया। विशिष्ट अतिथि एसओ आलोक कुमार, भाजपा नेता डा. डीएन कुशवाहा, एसआई अंकित सिंह, प्रधान प्रतिनिधि सिकंदर शर्मा, डा. आनंद यादव, डा. मायालाल शर्मा, राजू माली, रामसेवक प्रसाद, ईश्वरचंद गुप्त, राजनारायण मिश्र चुन्नू, अंशुमान मिश्र साहब, मुकेश यादव, राजू यादव, भोलू यादव, धर्मराज, अमित सिंह आदि उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक, जरूरतमंदों को अधिक से अधिक निःशुल्क कानूनी सहायता देने के निर्देश

कुशीनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भुवन ने शुक्रवार को अपने विश्राम कक्ष में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (एलएडीसीएस) के साथ समीक्षा बैठक कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सचिव ने निर्देशित किया कि एलएडीसीएस टीम अधिक से अधिक निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि न्यायालय से न्याय की अपेक्षा रखने वाले पात्र व्यक्तियों के मामलों की प्रभावी पैरवी करते हुए उनका पक्ष मजबूती से रखा जाए, ताकि उन्हें समयबद्ध न्याय मिल सके। सचिव ने जेल विजिट के दौरान ऐसे बंदियों से मुलाकात करने पर भी जोर दिया, जिनका कोई पैरवीकार नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि उनकी समस्याओं को समझकर उनके मुकदमों से संबंधित पत्रावलियों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए। बैठक में चीफ एलएडीसीएस लक्ष्मण पाठक, डिप्टी एलएडीसीएस राकेश कुमार सिंह, असिस्टेंट एलएडीसीएस आलोक चंद्र पाण्डेय तथा असिस्टेंट एलएडीसीएस महेंद्र यादव उपस्थित रहे।

नीट एंड क्लिन होगा नपा कुशीनगर, अध्यक्ष ने छः कूड़ा वाहनों का किया पूजन

- नगर और वार्डो को और स्वच्छता व बेहतर बनाया जाएगा- किरन जायसवाल
- नये वाहनों से कूड़े का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण होगा प्रभावी- ईओ अंकिता शुक्ला

कसया, कुशीनगर।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर पालिका परिषद कुशीनगर अध्यक्ष किरन जायसवाल ने स्वच्छ शहर, स्वस्थ शहर के संकल्प के साथ छः नये टीपर (कूड़ा ढुलाई वाहन) का विधिवत पूजन अर्चन कर सफाई विभाग को उपलब्ध कराया। शुक्रवार को नगर स्थित कान्हा गौ शाला में अध्यक्ष श्रीमती जायसवाल ने इन वाहनों का पूजन करने के पश्चात कहा कि नए वाहनों के आ जाने से शहर की सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा और कसया नगर और सभी वार्डो को नीट और क्लीन बनाने के संकल्प को बढ़ावा मिलेगा। यह केवल शुरुआत है। भविष्य में और अधिक आधुनिक उपकरण तथा मशीनरी लाकर स्वच्छता को और बेहतर बनाने की योजना है। नपा की अधिशासी अधिकारी अंकिता शुक्ला ने इस मौके पर कहा कि इन नये वाहनों से कूड़े का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण पहले से अधिक तेज और प्रभावी होगा। इससे सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। संचालन नपा के स्वच्छता प्रभारी श्रवण कुमार तिवारी ने किया। इस दौरान प्रधान लिपिक राजेश कुमार श्रीवास्तव, कमोद पांडेय, हरेंद्र यादव आदि सहित कर्मचारी उपस्थित रहे।

पटहेरवा में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश- नवागत थानाध्यक्ष प्रविन्द्र राय बोले

कानून से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं, हर फरियादी को मिलेगा त्वरित न्याय

पटहेरवा कुशीनगर।

थाना पटहेरवा के नवागत थानाध्यक्ष प्रविन्द्र राय ने गुरुवार को मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की जनता को अपना स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि आम नागरिकों और फरियादियों को सम्मानपूर्वक एवं त्वरित न्याय दिलाना उनकी कार्यशैली का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद एवं विश्वास कायम करना उनकी प्राथमिकता है। थाना आने वाले प्रत्येक फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाएगा और उसका निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी पीड़ित को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नवागत थानाध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा कि क्षेत्र में अपराध, अवैध गतिविधियों, नशे के कारोबार, गुंडागर्दी और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के लिए कोई जगह नहीं होगी। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करने वाले नागरिकों का पुलिस हमेशा सम्मान करेगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अपराध या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के सहयोग से ही अपराधमुक्त एवं सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है। थानाध्यक्ष प्रविन्द्र राय ने भरोसा दिलाया कि पटहेरवा थाना आम जनता के लिए 24 घंटे खुला है। पुलिस निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगी। उन्होंने लोगों से कानून का पालन करने तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की।

मेडिकल कालेज अस्पताल में मुस्तैदी- प्राचार्य व सीएमएस ने परखीं व्यवस्थाएं, समय पर मिलेंगे डॉक्टर

भर्ती मरीजों से सीधा संवाद कर जाना दवाओं और इलाज का हाल

देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और मरीज-अनुकूल बनाने के लिए प्रबंधन ने जमीनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. रजनी पटेल एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एच.के. मिश्रा ने संयुक्त रूप से अस्पताल परिसर का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट और स्वास्थ्य महानिदेशालय के उच्च मानकों के अनुरूप इमरजेंसी, ओपीडी, महिला एवं बाल चिकित्सालय (एमसीएच) और पंजीकरण काउंटरों की व्यवस्थाओं को परखा गया, ताकि सुदूर ग्रामीण अंचलों से आने वाले पीड़ितों को किसी भी स्तर पर असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान प्राचार्य डॉ. रजनी पटेल ने स्पष्ट किया कि अस्पताल आने वाले प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध उपचार मिलना चाहिए। उन्होंने ड्यूटी रोस्टर की समीक्षा करते हुए कड़े निर्देश दिए कि सभी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ अपने निर्धारित समय पर ओपीडी और वार्डों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। दवाओं की उपलब्धता की जांच करते हुए उन्होंने प्रभारियों को निर्देशित किया कि आवश्यक दवाओं का स्टॉक हमेशा दुरुस्त रखा जाए, जिससे मरीजों को बाहर से दवाएं न खरीदनी पड़ें। वहीं, सीएमएस डॉ. एच.के. मिश्रा ने विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर वहां भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधा संवाद किया। उन्होंने इलाज, वार्डों की साफ-सफाई और मिल रहे भोजन की गुणवत्ता के संबंध में फीडबैक लिया। तीमारदारों ने चिकित्सा प्रबंधकों को बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों का व्यवहार और उपचार की प्रक्रिया संतोषजनक है। सीएमएस ने सुरक्षा प्रभारियों को परिसर में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने और स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। प्रशासन के इस कड़े रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में अस्पताल की व्यवस्थाओं में और अधिक गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगा।

निकायों की लचर कार्यशैली पर डीएम नाराज, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रुकेगा वेतन

- ईओ को नियमित फील्ड में उतरकर जनसमस्याएं दूर करने के निर्देश
- हर निकाय की पांच प्रमुख बड़ी परियोजनाओं की जिलाधिकारी खुद करेंगे जांच

देवरिया।

नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं को पारदर्शी ढंग से धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक अहम समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने सभी ईओ को दोटूक हिदायत दी कि वे दफ्तरों से बाहर निकलकर नियमित रूप से फील्ड में जाएं और जनसमस्याओं का मौके पर समाधान करें। इसके साथ ही प्रशासनिक अनुशासन सुदृढ़ करते हुए जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि कोई भी अधिशासी अधिकारी बिना पूर्व सक्षम अनुमति के जिला मुख्यालय से नदारद पाया गया, तो उसका वेतन रोकने की कठोर दंडात्मक कार्रवाई तत्काल की जाएगी। बैठक में पारदर्शी सुशासन पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि निकायों में होने वाले सभी टेंडर नियमों के दायरे में पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जाएं। जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) की समीक्षा के दौरान उन्होंने ईओ को निर्देश दिया कि वे शिकायतों का केवल कागजी निस्तारण न करें, बल्कि कम से कम 25-25 प्रकरणों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करें। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में कायाकल्प योजना के तहत संसाधन बढ़ाए जाएं। स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने वार्डों में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य सत्रों में आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा मातृ-शिशु मृत्यु दर व मिसिंग डिलीवरी की नियमित समीक्षा करने को कहा। नगरीय विकास की दिशा में जिलाधिकारी ने सभी निकायों को मल्टी लेवल पार्किंग, सुव्यवस्थित टैक्सी स्टैंड और वेंडिंग जोन विकसित करने के साथ-साथ जल संरक्षण के लिए स्थानीय तालाबों के सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पांचवें राय वित्त आयोग के बजट से सीएचसी, तहसील परिसरों और सार्वजनिक शौचालयों का कायाकल्प कराया जाए। जिलाधिकारी ने घोषणा की कि सभी नगर पालिका क्षेत्रों की पांच-पांच बड़ी विकास परियोजनाओं का वे स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर काम की गुणवत्ता को परखेंगे। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह, ईओ नगर पालिका संजय तिवारी, एलबीसी नर्वदेश्वर कुमार सहित सभी निकायों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।

गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित, 30 सितंबर अंतिम तिथि

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार-2026 के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन एवं प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपदवासियों, सामाजिक संस्थाओं और संबंधित विभागों से योग्य व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित करने की अपील की है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन भारतीय मूल के नागरिकों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान दिया हो। पुरस्कार के लिए वही व्यक्ति पात्र होंगे, जो संबंधित वर्ष में सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवासरत रहे हों तथा पूर्व में इस पुरस्कार से सम्मानित न हुए हों। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों की जांच के बाद उन्हें शासन को भेजा जाएगा। आवेदन के साथ अभ्यर्थी के कार्यों का विस्तृत विवरण, उपलब्धियों से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने सभी विभागों, सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों से 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित प्रारूप में पात्र व्यक्तियों के नाम उपलब्ध कराने की अपील की है, ताकि समयबद्ध रूप से शासन को प्रस्ताव भेजे जा सकें।

ई-रिक्शा में लगी डिजिटल सेंध, चलते-चलते हो रहे हैं बंद, दिल्ली में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों ई-रिक्शा चालकों के साथ अजीबोगरीब और खतरनाक खेल खेला जा रहा है। कुछ मनचले और शरारती तत्व राह चलते ई-रिक्शा को एक मोबाइल एप के जरिये अचानक बंद कर रहे है। बीच सड़क पर अचानक वाहन बंद होने से चालक जहां परेशान हो रहे हैं, वहीं हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर बीते एक-दो दिनों से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें कार सवार या बाइक पर बैठे लोग ई-रिक्शा रोक देते हैं फिर इसे प्रैंक यानी मजाक का नाम दे रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी, संगम विहार, बदरपुर बॉर्डर, नई दिल्ली और पहाड़गंज जैसे व्यस्त इलाकों में अचानक से ई-रिक्शा बंद होने की घटना देखी जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ई-रिक्शा एसेंबल करने वाले इस एप का करते हैं इस्तेमाल। जहांगीरपुरी के रहने वाले सोहन कुमार ने बताया कि उनके भाई कुणाल कुमार ई-रिक्शा चलाते हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार दोपहर सवारी लेकर जाते समय अचानक

उनका रिक्शा बीच सड़क पर बंद हो गया। कुछ समझ में नहीं आया कि बैटरी पूरी चार्ज फिर ऐसा कैसे हुआ। सराय काले खां में रहने वाले ऑटो चालक महमूद का भी रिक्शा ऐसे ही बंद हो गया।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक, बैट-बीएमएस नाम का चीनी एप है। तकनीकी रूप से यह बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एप है। साइबर एक्सपर्ट सलाम रस्तोगी ने इसे ई रिक्शा एसेंबल करने वाली कंपनियां तकनीकी जांच के लिए इस्तेमाल करती है। इसमें ऑन, ऑफ और रिस्टार्ट के ऑप्शन होते है। इसका पता आम लोगों के चल गया जिससे यह दिक्कत हो रही है। दरअसल ब्लूटूथ वाली लिथियम-आयन बैटरी की निगरानी के लिए इसे डिजाइन किया गया है।

यह एप बैटरी का चार्ज, वोल्टेज, तापमान और सेहत जैसी जानकारियां भी दिखाता है। यह ब्लूटूथ लो एनर्जी (बीएलई) तकनीक पर काम करता है और इसकी रेंज 15 मीटर तक होती है। यह ऐप हर ई-रिक्शा को बंद नहीं कर सकता। यह केवल उन्हीं ई-रिक्शा पर काम करता है जिनमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली चीनी लिथियम बैटरी लगी है और जिसका ब्लूटूथ खुला हुआ है। जिन ई-रिक्शा में पारंपरिक लेड-एसिड (तेजाब वाली) बैटरी का इस्तेमाल होता है, उन्हें इस ऐप से न तो बंद किया जा सकता है और न ही चालू। जानकारों का कहना है कि चालकों को बैटरी का ब्लूटूथ पासवर्ड बदल लेना चाहिए या मिस्त्री से कहकर इसे पूरी तरह डिसेबल (बंद) करवा देना चाहिए, ताकि वे इस मानसिक उत्पीड़न और हादसे से बच सकते है। यदि चलता हुआ वाहन अचानक बंद हो जाए तो पीछे से आ रही गाड़ी टक्कर मार सकती है यात्री गिर सकते है, चालक नियंत्रण खो सकता है। व्यस्त सड़क पर बड़ा हादसा हो सकता है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके पास इस तरह की अभी कोई शिकायत नहीं मिली है।

उनका कहना है कि हो सकता है संबंधित ऐप का प्रमोशन करने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक फैलाई जा रही हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस तरह का कोई भी मामला उनके संज्ञान में आता है, तो दिल्ली पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी।

प्रधानमंत्री ने राम मंदिर निर्माण का श्रेय लिया, चढ़ावा चोरी की जिम्मेदारी भी लेनी होगी कांग्रेस

नई दिल्ली ।

कांग्रेस ने शुक्रवार को अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में सच्चाई छिपाने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंदिर निर्माण का श्रेय लिया है तो अब उन्हें इस प्रकरण की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। पार्टी प्रवक्ता रागिनी नायक ने यहां संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि राम मंदिर में 40 दिनों के भीतर 70 बार चोरी हुई, लेकिन इस मामले में अब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा, भाजपा

सरकार ने दबाव में आकर एसआईटी का गठन किया गया लेकिन आखिर क्या कारण है कि उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है? नायक ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का श्रेय लिया था, लेकिन अब चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा, जब श्रेय लिया है तो चोरी की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। यह जनता के साथ विश्वासघात है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बड़े मामलों में अक्सर छोटे लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, जबकि बड़ी मछलियों को बचा लिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में भाजपा के कुछ लोग इसे आपसी मामला बताकर निपटाने की बात कर रहे हैं, जबकि मंदिर में देश के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार चढ़ावा चढ़ाया है। नायक ने कहा, यह किसी की बपौती नहीं है। प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर जनता के सामने आकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने मांग की कि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और मामले की निष्पक्ष तथा पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए।

पीएम मोदी आज राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे

नेशनल डेस्क । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। इस दौरान वह बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परिसर और साणंद में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण केन्द्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर से राजस्थान के अपने दौरे की शुरुआत करेंगे, जहां वह जोधपुर हवाईअड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के मकसद से संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। आधिकारिक बयान के मुताबिक, 480 करोड़ रुपये की लागत से बने नए हवाईअड्डा टर्मिनल को सालाना 20 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता के

साथ तैयार किया गया है। 23,000 वर्ग मीटर से ज्यादा इलाके में फैले इस टर्मिनल में यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं और कई अन्य विशेषताएं शामिल हैं। बयान के अनुसार, संशोधित उड़ान योजना के तहत, केंद्र सरकार ने अगले 10 वर्षों में क्षेत्रीय विमानन सेवाओं का विस्तार करने के लिए 28,840 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। एक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री बाद में बालोतरा जाएंगे, जहां वह लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान के बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन अप्रैल में मोदी द्वारा किया जाना था, लेकिन उद्घाटन से एक दिन पहले भीषण आग लगने के कारण इसे टाल दिया गया था। विज्ञप्ति के अनुसार, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम वाली यह रिफाइनरी 79,450 करोड़ रुपये की लागत से बनी है। मोदी जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी अनुमानित लागत 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। 41 किलोमीटर लंबे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर में 36 स्टेशन होंगे। प्रधानमंत्री चूरू-सादुलपुर और चूरू-रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। इसके अलावा, वह एनएच-125ए जोधपुर रिंग रोड खंड-2 (करवार-डांगियावास) परियोजना के तहत फोर-लेन सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। मोदी एसजेवीएन लिमिटेड के 1,000 मेगावाट क्षमता वाली बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को भी जनता को समर्पित करेंगे। दौरे में प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में हाल ही में भर्ती हुए लगभग 54,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का पहला बयान

दोषियों को सजा मिले

चोरी की घटना से राम भक्तों की श्रद्धा को आघात पहुंचा- दत्तात्रेय होसबाले

नई दिल्ली । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह (महासचिव) दत्तात्रेय होसबाले ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की घटना ने पूरे समाज की भावनाओं और आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि हिंदू विरोधी और राष्ट्रविरोधी ताकतें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का फायदा उठाकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पूरे हिंदू समाज से भी अपील की कि वह इस कठिन समय में धैर्य और संयम बनाए रखे, ताकि इस तरह की सभी साजिशों को

विफल किया जा सके। होसबाले ने एक्स पर एक बयान में कहा, अयोध्या स्थित श्रीराम लला मंदिर में रखे दानपात्रों से चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे समाज और रामभक्तों की भावनाओं तथा आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा, इस घटना से हम सभी बहुत दुखी और आक्रोशित हैं। होसबाले ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत पूरे हिंदू समाज को न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि वह इस अत्यंत निंदनीय घटना को असाधारण मामला मानते हुए मंदिर के प्रबंधन और संचालन में मौजूद सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मौजूदा भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति समाप्त होनी चाहिए। होसबाले ने कहा, इस संबंध में हमें अपेक्षा है कि मंदिर प्रबंधन और सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष तथा करोड़ों रामभक्तों के समर्पण, त्याग और बलिदान के कारण पूरे हिंदू समाज की श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र है। उन्होंने कहा, हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन के लिए पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और शुचिता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिन्दू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा।

जैश-ए-मोहम्मद की आतंकी साजिश फेल!

गुजरात एटीएस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली।

पाकिस्तान अभी भी भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहता है. उसका आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद भारत में नेटवर्क फैलाने की कोशिश में था, लेकिन गुजरात एटीएस ने साजिश को नाकाम कर दिया. एटीएस ने शुक्रवार (3 जुलाई) को गुजरात और मध्य प्रदेश से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. ये देश में जैश के नेटवर्क को फैलाने का काम कर रहे थे. गुजरात और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अहमद अब्दुल्ला गाजीवाला, इब्राहिम मोहम्मद हुसैन घाघा, मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला, जकारिया दुरानी मोहम्मद अम्मार घाघा, मुफ्ती फौजान इस्माइल दीवा, मोहम्मद अमीन शेरा, मोहम्मद अब्दुल रहमान सावदी और बिलाल दुरानी मोहम्मद अम्मार घाघा के रूप में की गई है. एटीएस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपी कथित तौर पर संगठन की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में एक सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे. आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के सेक्शन 13, 17, 18, 38 और 39 के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 148 और 61 को भी लगाया गया है. जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना साल 2000 में मसूद अजहर ने की थी. यह आतंकी संगठन भारत में अभी तक छह बाहर हमले करवा चुका है. जैश ने अप्रैल 2000 में सेना के हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला करवाया था. 17 साल के आतंकी ने जम्मू कश्मीर में इस हमले को अंजाम दिया था. इसके बाद अक्तूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला करवाया गया. इसके बाद पठानकोट एयरबेस पर जनवरी 2016 में हमला हुआ. उरी के सेना हेडक्वार्टर पर सितंबर 2016 में अटैक हुआ. पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर भी अटैक हुआ था.

खामेनेई का अंतिम संस्कार शुरू -14 महीने की पोती का ताबूत भी रखा गया; श्रद्धांजलि देने आए राष्ट्रपति पजशकियान रो पड़े

तेहरान । ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो गई है। खामेनेई के साथ उनकी 14 महीने की पोती, पत्नी, बेटी और दामाद को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। खामेनेई की पोती के छोटे से ताबूत के पास उसकी तस्वीर भी रखी गई है। तेहरान के मोसल्ला परिसर में अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूत रखे गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान समेत देश का शीर्ष नेतृत्व तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचा। इस दौरान पजशकियान भावुक होकर रो पड़े। उनके साथ मौजूद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और कई सैन्य

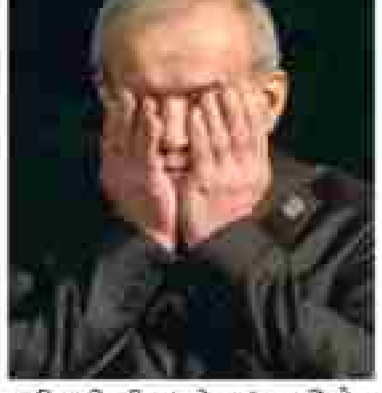

अधिकारी भी अपने आंसू नहीं रोक सके। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई थी। 131 दिन बाद, 9 जुलाई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी- हलाला और तीन तलाक के नाम पर शोषण बर्दाश्त नहीं, यह सुनियोजित गैंगरेप

प्रयागराज ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह, हलाला और 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने साफ लफ्जों में कहा है कि व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) की आड़ लेकर महिलाओं के यौन शोषण की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इन प्रथाओं को समाज का काला पन्ना करार देते हुए कहा कि ये पूरी तरह से संवैधानिक मूल्यों, लैंगिक समानता और मानवीय गरिमा के खिलाफ हैं।

न्यायालय के मुताबिक, ऐसे कृत्य न केवल कानूनी तौर पर संगीन अपराध है, बल्कि समाज की सामूहिक अंतरात्मा को भी झकझोर कर रख देते है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और

न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पीड़िता के पूर्व पति, चाचा और मौलाना समेत अन्य आरोपियों की याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। इन आरोपियों ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि क्रिमिनल लॉ के सामने पर्सनल लॉ की दलीलें नहीं दी जा सकतीं, जब तक कि कानून खुद इसकी छूट न दे। पहली नजर में यह मामला एक नाबालिग बच्ची के साथ सुनियोजित तरीके से किए गए सामूहिक दुष्कर्म का नजर आता है, जिसकी गहराई से जांच होना बेहद जरूरी है। रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर जांच को शुरुआती चरण में ही ठप नहीं किया जा सकता।

क्या है पूरा मामला?

यह झकझोर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के सैदनगली थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कम उम्र में जबरन निकाह, तीन तलाक और फिर हलाला के नाम पर सिलसिलेवार तरीके से हुए यौन शोषण की दर्दनाक कहानी बयां की है।

एफआईआर के मुताबिक घटनाक्रम इस तरह है-

- अप्रैल 2015- पीड़िता की उम्र जब महज 15 साल (नाबालिग) थी, तब उसका निकाह जबरन मुख्य आरोपी अजहर नवाज के साथ करा दिया गया।

- जनवरी 2016- शादी के कुछ ही महीनों बाद आरोपी नवाज ने उसे तीन तलाक दे दिया।

- नवंबर 2016- नवाज ने दोबारा शादी की इच्छा जताई, जिसके लिए पीड़िता को सह-आरोपी मौलाना कयूम के साथ निकाह हलाला करने पर मजबूर किया गया। तब पीड़िता 16 साल की थी और मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में उसने कहा कि उसे हलाला का मतलब तक नहीं पता था, वहां उसके साथ रेप किया गया।

- साल 2017- हलाला की प्रक्रिया के बाद नवाज ने उससे दोबारा निकाह किया, लेकिन चार साल बाद फिर तलाक देकर दूसरी महिला से शादी कर ली।

राम मंदिर दान घोटाला- उद्धव ने 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन का किया एलान

नई दिल्ली । अयोध्या राम मंदिर में कथित दान गबन मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पांच जुलाई से राम रक्षा आंदोलन शुरू करने का एलान किया है। वहीं, भाजपा ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार किया है।

उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि पांच जुलाई (रविवार) को मुंबई के दादर स्थित हनुमान मंदिर में शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्ता और समर्थक एकत्र होंगे। वहां हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और भाजपा से अयोध्या राम मंदिर में कथित दान गबन मामले की जिम्मेदारी लेने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा, राम मंदिर में कथित बड़े पैमाने पर हुई इस चोरी से जो भी लोग

आहत हैं, वे हमारे साथ जुड़ें और भाजपा से जवाब मांगें। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि केंद्र और कई राज्यों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद देश में अव्यवस्था है और जनता के मुद्दों के प्रति उदासीनता दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में अविभाजित शिवसेना समेत कई हिंदुओं ने हिस्सा लिया था। इस दौरान कारसेवकों पर अत्याचार हुए, गोधरा ट्रेन कांड, अहमदाबाद दंगे और मुंबई सिलसिलेवार बम धमाके जैसी घटनाएं हुईं। उनका आरोप था कि भाजपा ने इन घटनाओं का राजनीतिक लाभ उठाया और अब बेलगाम सत्ता का आनंद ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर विपक्षी विधायकों की टूट और कथित खरीद-फरोख्त कराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या सत्तारूढ़ दल ऑपरेशन राम मंदिर चला रहा है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चा में सामने आए राम मंदिर के दान में कथित गबन के आरोपों का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या कथित तौर पर चोरी किया गया पैसा विपक्षी नेताओं को अपनी ओर लाने में इस्तेमाल किया गया।

टीएमसी मुख्यालय पर ऋतब्रत गुट ने किया कब्जा

कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर चल रही राजनीतिक खींचतान ने शुक्रवार नया मोड़ ले लिया। विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने कोलकाता स्थित पार्टी के संगठनात्मक मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। यह घटनाक्रम उस दावे के एक दिन बाद सामने आया है, जब गुट ने चुनाव आयोग के समक्ष पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश किया था।

बागी गुट की कार्यालय में बैठक

मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र स्थित यह कार्यालय वर्ष 2022 से टीएमसी का संचालन मुख्यालय रहा है। पार्टी का मूल कार्यालय पुनर्निर्माण के चलते बंद है, जिसके बाद बाद संगठन यहां से काम कर रहा था। अब इस कार्यालय से संचालन शुरू कर बागी गुट ने खुद को संगठन का असली प्रतिनिधि साबित करने की कोशिश की है। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट के बागी नेता संदीपन साहा ने कहा, यह हमारा ऑफिस है, हमारी जिम्मेदारी है। पार्टी की भविष्य की गतिविधियां यहीं होंगी। ऋतब्रत बनर्जी वरिष्ठ नेताओं फिरहाद हकीम, जावेद खान, संदीपन साहा और असरुज्जमान के साथ कार्यालय पहुंचे और वहां बैठक की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उनका गुट ही «वास्तविक» तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। गुट के नेताओं

***कुणाल घोष बोले- पुलिस की मदद से जबरन ताला लगाया**

का कहना है कि उन्होंने कार्यालय के मालिकों के साथ आवश्यक समझौते की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब से इसी कार्यालय से पार्टी का संचालन करेंगे। हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद ऋतब्रत बनर्जी और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के बीच वैध नेतृत्व को लेकर विवाद लगातार गहराता जा

रहा है। दोनों पक्ष खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं। अब तक यह विवाद संगठनात्मक दावों, प्रस्तावों और कानूनी तर्कों तक सीमित था, लेकिन शुक्रवार को मुख्यालय से संचालन शुरू करना बागी गुट की ओर से एक अहम राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन स्थित यह कार्यालय किराये पर लिया गया था, जब पार्टी ने पुनर्निर्माण के चलते ईएम बाइपास स्थित अपने पुराने मुख्यालय को खाली किया था।

टीएमसी ऑफिस पर कब्जा किए जाने के बाद नेता कुणाल घोष ने कहा, आज जिन लोगों ने तृणमूल भवन में जबरन घुसकर ताला लगाया, उनके खिलाफ हमने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। परिसर में ताला लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। पार्टी से निकाले गए लोगों को कार्यालय में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। हमने इस बारे में पहले ही पुलिस से अनुरोध किया था। हम चाहें तो लगाया गया ताला तोड़ सकते थे, लेकिन हमने कोई गैरकानूनी या गैर-जिम्मेदाराना कदम नहीं उठाया। पुलिस से अपील के बावजूद उन्होंने उन लोगों को ताला लगाने दिया और फिर उसी ताले की सुरक्षा में खड़ी रही। जब हमने पुलिस से हमें अंदर जाने देने को कहा, तब स्थानीय पुलिस, आरएएफ और केंद्रीय बल वहीं खड़े रहे। यह तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश है। बंगाल की जनता और तृणमूल के कार्यकर्ता सब कुछ देख रहे हैं।

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, अगर पार्टी के किसी विधायक को पार्टी ऑफिस आना है, तो यह उनका अधिकार है। ये ताले क्यों लगाए जा रहे हैं?... जब तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले होते हैं और उन्हें मदद की जरूरत होती है, तो ये लोग अपने चुनाव क्षेत्रों में नहीं जाते। इसके बजाय वे किसी और के हाथों की कठपुतली बन गए है और यह सब कर रहे है। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कहा, केंद्रीय बल 15 मिनट के भीतर टीएमसी के एक खास गुट की सुरक्षा के लिए पहुंच गए। इससे साबित होता है कि ये लोग भाजपा की बी-टीम की तरह काम कर रहे हैं। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है। बंगाल में हमारी पार्टी के कम से कम एक लाख कार्यालय बंद हैं और हमारे कार्यकर्ता वहां बैठ भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें उत्पीड़न, गुंडागर्दी और पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए भाजपा का कोई नेता नहीं पहुंचा। पुलिस ने कहा कि वह मकान मालिक को बुलाकर समझौते की जांच करेगी। हमारे पास बगल वाले कमरे की चाबी है, फिर भी हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।